के. एस. के.

नागरिक विविध

जस्टिस प्रेम चंद पंडित और जस्टिस भोपिंदर सिंह ढिल्लों के समक्ष

याचिकाकर्ता - फर्म हनुमान दल एवं जनरल मिल्स, बालसमंद

रोड, हिसार

बनाम

प्रतिवादी - द. मार्केट कमेटी, हिसार, आदि

1972 की सिविल रिट संख्या 1183

17 मई 1973.

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम (1961 का XXIII) - धारा 5 और 6 - धारा 6(4) - चाहे धारा 5 या 6 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन पूर्वनिर्धारित हो - उपधारा में "किसी भी चूक के बावजूद प्रकाशित करने के लिए" शब्द - का अर्थ -अधिसूचना से किसी विशेष क्षेत्र को हटाने की दलील क्या बाध्यकारी परिस्थितियों से प्रमाणित की जानी है - याचिका की स्वीकृति - क्या अधिसूचना में क्षेत्र को शामिल करने का परिणाम है - क़ानून की व्याख्या - किसी क़ानून में शब्दों का व्याकरणिक और सामान्य अर्थ — क्या टाला जा सकता है ।

माना गया कि पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 की धारा 6 की उप-धारा (4) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अधिनियम की धारा 5 या 6 के तहत आधिकारिक गजट में प्रकाशित अधिसूचना पूरी तरह से लागू होगी जिसका अर्थ है कि यह प्रावधान मानता है कि अधिनियम की धारा 5 या 6 के तहत एक अधिसूचना, जैसा भी मामला हो, पहले ही जारी की जा चुकी है और यह वह जारी अधिसूचना है जिसमें चूक, अनियमितता या दोष को नजरअंदाज किया जाना है। इस उप-धारा में "प्रकाशित करने में किसी भी चूक के बावजूद" शब्दों का मतलब यह नहीं है कि अधिनियम की धारा 5 या 6 के तहत अधिसूचना, जैसा भी मामला हो, प्रकाशित नहीं की गई है, लेकिन उनका मतलब यह है कि जैसा कि शुरुआत में उल्लिखित है। अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 4 की सजा जारी कर दी गई है और इसके प्रकाशन में कोई चूक या प्रकाशन में अनियमितता या दोष आ गया है, जिसे नजरअंदाज करना होगा। यदि इन शब्दों का अर्थ निकाला जाए तो अधिसूचना का प्रकाशित न होना भी। यह बेतुकेपन की ओर ले जाएगा क्योंकि उस स्थिति में धारा 6 की उपधारा (4) का पहला भाग निरर्थक हो जाता है और उस भाग पर कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता है।

माना गया कि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि क्या किसी विशेष क्षेत्र के संबंध में अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन में कोई

चूक हुई है और क्या सभी उपस्थित परिस्थितियां एक निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि ऐसा हुआ है उस मामले में एक चूक अकेले अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जारी अधिसूचना वैध होगी और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संबंधित क्षेत्र को प्रावधानों के कारण अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में अधिसूचित माना जाएगा। अधिनियम की धारा 6(4) के. यह दलील कि अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में किसी विशेष क्षेत्र के प्रकाशन में चूक हुई है, को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी याचिका उठाने वाले पक्ष को ठोस परिस्थितियों में अपनी दलील को प्रमाणित करना होगा कि यह वास्तव में एक चूक थी। यदि न्यायालय संतुष्ट है कि यह एक चूक थी, तो धारा 6 की उप-धारा (4) के प्रावधान को लागू करना होगा और जो क्षेत्र चूक के कारण धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना से बाहर रह गया था, उसे माना जाएगा बिक्री अधिसूचना में शामिल किया जाना है. एक बार ऐसा हो जाने पर, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) का पूर्ण अनुपालन होगा।

माना गया कि व्याकरण के सामान्य नियम को एक अपरिवर्तनीय नियम के रूप में नहीं माना जा सकता है जिसे हमेशा और हर मामले में संदर्भ की परवाह किए बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि संदर्भ निश्चित रूप से सुझाव देता है कि व्याकरण का प्रासंगिक नियम अनुपयुक्त है, तो संदर्भ की आवश्यकता व्याकरण के नियम पर हावी होनी चाहिए। इसलिए

बेतुकेपन या विसंगति से बचने के लिए, कुछ परिस्थितियों में किसी क़ानून में शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ से भी बचा जा सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत संशोधित याचिका में प्रार्थना की गई है कि एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें यह घोषित किया जाए कि प्रतिवादी संख्या । के पास किए गए लेनदेन के संबंध में याचिकाकर्ता फर्म से बाजार शुल्क लगाने और वसूलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हदबास्ट 146 के हिसार क्षेत्र (नगरपालिका क्षेत्र सहित) और हिसार (नगरपालिका क्षेत्र सहित) हदबास्ट 146 के क्षेत्र में किए गए लेनदेन के संबंध में याचिकाकर्ता फर्म से किसी भी बाजार शुल्क को लगाने या वसूलने से प्रतिवादी नंबर 1 को रोकना। प्रत्येक शुल्क का भुगतान न करने के लिए याचिकाकर्ता फर्म के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करना और प्रतिवादी नंबर 1 समिति को इस रिट याचिका का निर्णय होने तक ऐसे शुल्क का भुगतान न करने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकना।

याचिकाकर्ता के वकील आनंद स्वरूप । प्रतिवादी नंबर 1 के लिए वकील पी. एस. जैन और वी. एम. जैन।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए सी. डी. दीवान, अतिरिक्त महाधिवक्ता, (हरियाणा)

निर्णय

जस्टिस ढिल्लों- यह निर्णय सात संबंधित रिट याचिकाओं क्रमांक 1183 से 1188, 1972 और 194, 1973 का निपटारा कर देगा क्योंकि इन सभी याचिकाओं में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उठते हैं।

(2) संक्षेप में इन रिट याचिकाओं को जन्म देने वाले तथ्य यह हैं कि इन सभी याचिकाओं में याचिकाकर्ता हिसार नगर समिति हेडबास्ट नंबर 146 की नगरपालिका सीमा के भीतर कृषि उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण का व्यवसाय कर रहे हैं। और पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत लाइसेंसधारी हैं। अधिनियम की धारा 5 के तहत, राज्य सरकार ने 18 सितंबर, 1961 को एक अधिसूचना जारी की, जो 22 सितंबर, 1961 को प्रकाशित हुई, जिसकी प्रति रिट याचिका संख्या 1183/1972 के साथ अनुबंध 'ए' है, जिसमें उक्त अधिसूचना में उल्लिखित गांवों की राजस्व सम्पदा में उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण पर नियंत्रण करने के अपने इरादे की घोषणा की गई है।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि उक्त अधिसूचना में 149 गांवों के नाम शामिल हैं जिनमें बीर हिसार हदबस्त नंबर 145 भी शामिल है और जो क्षेत्र अब नगरपालिका समिति हिसार की

सीमा के भीतर आता है वह हदबस्त नंबर 146 है और उक्त हदबस्त का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त अधिसूचना. 5 जून, 1962 को, राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 6(1) के तहत अधिसूचना जारी की, जिसमें अधिसूचना से जुड़ी अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्र को मार्केट कमेटी, हिसार का अधिसूचित बाजार क्षेत्र घोषित किया गया। उक्त अधिसूचना की प्रति 1972 की रिट याचिका संख्या 1183 के साथ अनुबंध 'बी' है। यह बताया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना, अनुबंध 'ए', जिसमें हदबास्ट संख्या 145, बीर हिसार शामिल है। 149 गांवों के नाम और हैडबास्ट नंबर, जिन्हें मार्केट कमेटी, हिसार के बाजार क्षेत्र में शामिल करने का इरादा था, जबकि अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जारी अधिसूचना में, जिसमें हैडबास्ट नंबर 146 भी शामिल है। बाजार क्षेत्र में शामिल गांवों की कुल संख्या 169 है। 30 अक्टूबर, 1962 को, पंजाब सरकार ने हिसार में एक मार्केट कमेटी की स्थापना के लिए अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत अधिसूचना जारी की, जिसे पंजाब सरकार के राजपत्र दिनांक 9 नवंबर, 1972 में प्रकाशित किया गया था। उसी रिट याचिका के साथ 'सी' उक्त अधिसूचना की प्रति संलग्न है । 3 अप्रैल, 1964 को, अधिनियम की धारा 5 के तहत एक और अधिसूचना, जिसमें हिसार (नगरपालिका क्षेत्र सहित) हैडबास्ट नंबर 146 क्षेत्र में कृषि उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण पर नियंत्रण रखने के राज्य सरकार के इरादे की घोषणा की गई थी। जाहिर तौर पर चूक को कवर करने के लिए, पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। उक्त अधिसूचना की प्रति 1972 की रिट

याचिका संख्या 1183 के साथ अनुबंध 'डी' है। 28 अगस्त, 1964 को अधिसूचना अनुबंध 'डी' के संदर्भ में अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत एक और अधिसूचना पंजाब द्वारा प्रकाशित की गई थी। सरकारी राजपत्र में सरकार ने बाजार समिति, हिसार के लिए अधिसूचित बाजार क्षेत्र के हिस्से के रूप में तहसील और जिला हिसार में क्षेत्र हिसार (नगरपालिका क्षेत्र सहित) हदबास्ट नंबर 146 की घोषणा की है। उक्त अधिसूचना की प्रति रिट याचिका संख्या 1183/1972 के साथ अनुबंध 'ई' है।

(3) रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उन सभी ने कृषि उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए अधिनियम के तहत बाजार समिति, हिसार से लाइसेंस लिया था और परिणामस्वरूप अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, वे मार्केट कमेटी, हिसार को मार्केट फीस का भुगतान कर रहे थे। वर्तमान रिट याचिकाओं में अब पहली बार यह दावा किया गया है कि चूंकि वर्ष 1961 में अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में हिसार नगरपालिका क्षेत्र हेडबस्ट नंबर 146 का नाम प्रकाशित नहीं किया गया था, इसलिए सी.डब्ल्यू. के साथ 'ए' को हटा दिया गया है। क्रमांक 1183 सन् 1972 अत: उक्त क्षेत्र को अधिनियम की धारा 6 परिशिष्ट 'बी' के अंतर्गत जारी अधिसूचना में सम्मिलित नहीं किया जा सका तथा ऐसा न हो पाने के कारण धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत मण्डी समिति की स्थापना की गयी अधिनियम के अनुसार, जिस

क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र हिसार हदबस्त नंबर 146 के रूप में जाना जाता है, वह अवैध है, और इसलिए, नगरपालिका क्षेत्र हिसार हदबस्त नंबर 146 को मार्केट कमेटी, हिसार के बाजार क्षेत्र में नहीं माना जाना चाहिए और हिसार हदबस्त नंबर 146 की नगरपालिका सीमा के भीतर अपना व्यवसाय करने वाले डीलर मार्केट कमेटी से कोई लाइसेंस लेने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं और इस तरह वे मार्केट शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि मार्केट कमेटी, हिसार के पास लेनदेन करने वाले व्यक्तियों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हदबास्ट नंबर 146, नगरपालिका क्षेत्र, हिसार के भीतर कृषि उपज की बिक्री, खरीद, भंडारण और प्रसंस्करण में, क्योंकि यह बाजार समिति, हिसार के बाजार क्षेत्र में शामिल नहीं है।इसलिए, इन रिट याचिकाओं में प्रार्थना की गई है कि एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें यह घोषित किया जाए कि प्रतिवादी बाजार समिति को नगरपालिका क्षेत्र में किए गए व्यवसाय के संबंध में याचिकाकर्ताओं से बाजार शुल्क लगाने और वसूलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हिसार हदबास्ट नंबर 146 और मार्केट कमेटी को उक्त मार्केट फीस का भुगतान न करने पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका जाए और साथ ही मार्केट कमेटी को गलत धारणा के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले ही भुगतान की गई मार्केट फीस वापस करने के लिए कहा जाए।

(4) यह बताया जा सकता है कि हरियाणा राज्य ने 1972 के हरियाणा अधिनियम संख्या 12 पर भी भरोसा किया है, जो राज्य सरकार के अनुसार बाजार शुल्क की वसूली और संग्रह को वैध बनाने के लिए हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि भले ही तर्क के लिए, यह स्वीकार किया जाए कि अधिसूचनाओं के प्रकाशन में कुछ प्रक्रियात्मक दोष है और कुछ कानूनी खामियां आ गई हैं, फिर भी, मान्यता के अनुसार, बाजार शुल्क का आरोपण और संग्रहण किया जाएगा। 1972 का अधिनियम संख्या 12 वैध है और याचिकाकर्ताओं का पहले से भुगतान किए गए बाजार शुल्क की वापसी का दावा इस आधार पर खारिज होने की संभावना है। गुण-दोष के आधार पर, मार्केट कमेटी, हिसार, जिसका कार्यालय और मुख्य मार्केट यार्ड हदबास्ट नंबर 146 के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है, द्वारा यह दावा किया गया है कि यह विवाद वाले क्षेत्र और क्षेत्र के लिए कानूनी रूप से गठित मार्केट कमेटी है। म्यूनिसिपल कमेटी, हिसार हदबस्त नंबर 146 स्वयं मार्केट कमेटी, हिसार के बाजार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी याचिकाकर्ताओं ने मार्केट कमेटी, हिसार से लाइसेंस लिया था और कई वर्षों से बाजार शुल्क का भुगतान कर रहे थे। इसलिए, यह दलील दी जाती है कि इन याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है। आगे यह दावा किया गया है कि अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना में एक छोटी सी चूक, यदि कोई हो, को अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के प्रावधानों और चूक, यदि कोई हो, को ध्यान

में रखते हुए नजरअंदाज किया जाना चाहिए। , तकनीकी और प्रक्रियात्मक प्रकृति का है, जिसे उपर्युक्त प्रावधानों के मद्देनजर माफ किया जाना चाहिए।

(5) पक्षों के लिए विद्वान वकील की दलीलों की सराहना करने के लिए, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 5, 6(1), 6(4), 11 और 12, नीचे पुन: प्रस्तुत की गई हैं : -

"5. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे कृषि उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण पर नियंत्रण रखने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है और ऐसे क्षेत्र में जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसी अधिसूचना में कहा जाएगा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट तीस दिनों से कम की अवधि के भीतर राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार किया जाएगा।"

"6(1) धारा 5 के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद और ऐसी अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और किसी अन्य तरीके से विहित किया जाए, धारा 5 या उसके किसी भाग के अंतर्गत अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के

लिए धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को अधिसूचित बाजार क्षेत्र घोषित किया जाए।

(2) * * * * * *

(3) * * * * * *

(4) संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा या धारा 5 के तहत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना पूरी ताकत और प्रभाव वाली होगी, भले ही इसके प्रकाशन में कोई चूक हो, या इसके प्रकाशन में कोई अनियमितता या त्रुटि हो। धारा या धारा 5 के तहत, जैसा भी मामला हो।"

11. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक अधिसूचित बाजार क्षेत्र के लिए एक बाजार समिति स्थापित करेगी और उसका मुख्यालय निर्दिष्ट करेगी।

“12. (1) एक समिति में नौ या सोलह सदस्य शामिल होंगे जैसा कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले में निर्धारित कर सकती है, जिनमें से एक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होगा।

बशर्ते कि जहां एक अधिसूचित बाजार क्षेत्र में एक सहकारी समिति अस्तित्व में है, समिति में, जैसा भी मामला हो, दस या सत्रह सदस्य शामिल होंगे।

(2) शेष सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार अधिसूचना द्वारा नामांकित किया जाएगा:

(ए) यदि समिति में नौ सदस्य होते हैं, तो नामांकित किया जाएगा-

(i) अधिसूचित बाजार क्षेत्र के उत्पादकों में से पांच सदस्य;

(ii) धारा 10 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से दो सदस्य; और

(iii) धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से एक सदस्य;

(बी) यदि समिति में दस सदस्य शामिल हैं, तो खंड (ए) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट सदस्यों के अलावा, (बी) यदि समिति में दस सदस्य शामिल हैं, तो खंड (ए) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट सदस्यों के अलावा, सह-प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य नामित किया जाएगा। को-ऑपरेटिव सोसायटी का सह-प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य नामित किया जाएगा।

(सी) यदि समिति में सोलह सदस्य होते हैं, तो नामांकित किया जाएगा-

(i) अधिसूचित बाजार क्षेत्र के उत्पादकों में से नौ सदस्य;

(ii) धारा 10 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से चार सदस्य; और

(iii) धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से दो सदस्य;

(डी) यदि समिति में सत्रह सदस्य होते हैं, तो खंड (सी) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट सदस्यों के अलावा, (डी) यदि समिति में सत्रह सदस्य होते हैं, तो खंड (सी) के उप-खंड (i), (ii) और (iii) में निर्दिष्ट सदस्यों के अलावा, सह-प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य नामित किया जाएगा। को-ऑपरेटिव सोसायटी का सह-प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य नामित किया जाएगा।

बशर्ते कि, जहां खंड (ए) के उप-खंड (iii) या खंड (सी) के उप-खंड (iii) के मामले में, धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त कोई व्यक्ति नहीं है या ऐसे व्यक्तियों की संख्या उन लोगों से कम है नामांकित करने की आवश्यकता है, कमी को धारा 10 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से नामांकित करके पूरा किया जाएगा।

(3) समिति द्वारा इस अधिनियम के तहत किया गया कोई भी कार्य या की गई कार्यवाही केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगी-

(ए) समिति के गठन में कोई रिक्ति या दोष

(बी) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नामांकन में कोई दोष या अनियमितता; या

(सी) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई दोष या अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करती है।

(4) इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अधीन, धारा 3 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अयोग्यताएं किसी समिति का सदस्य बनने के प्रयोजनों के लिए भी लागू होंगी।

(5) 11 मई, 1970 से -

(ए) ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कार्य करने वाली प्रत्येक समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित हों या अन्यथा, ऐसे सदस्यों के रूप में पद धारण करना बंद कर देंगे; और

(बी) राज्य सरकार इस कार्रवाई के प्रावधानों के अनुसार समितियों का गठन करेगी:

बशर्ते कि राज्य सरकार, जब तक ऐसी समितियों का गठन नहीं हो जाता है और उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुने नहीं जाते हैं, तब तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यान्वित करने के लिए इस संबंध में ऐसी समितियों के कार्य उपयुक्त माने जा सकते हैं ।

स्पष्टीकरण.- खंड (बी) के परंतुक के प्रयोजन के लिए उपधारा (5) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किया गया है ऐसी शुरुआत से पहले राज्य सरकार धारा 36 के अंतर्गत किसी समिति के कार्यों को निष्पादित करने के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा नियुक्त व्यक्ति माना जाएगा राज्य सरकार शक्तियों का प्रयोग और निष्पादन करेगी उन समितियों के कार्य जिनके लिए वे थीं नियुक्त किया गया।"

(6) इन प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कृषि उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण पर नियंत्रण रखने के लिए बाजार समिति की स्थापना के लिए बाजार क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। बाजार क्षेत्र यह है कि राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 5 के तहत एक अधिसूचना जारी करके अपना इरादा स्पष्ट करना होगा वह क्षेत्र जिस पर वह कृषि उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण आदि पर नियंत्रण रखना चाहता है उन कृषि उपजों को अधिसूचित करने के लिए भी, जिनके संबंध में खरीद, बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण को नियमित किया जाना है अधिसूचना में निर्दिष्ट कम से कम 30 दिन के भीतर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करना । अधिनियम की धारा 5 के तहत एक अधिसूचना प्राप्त होने के बाद और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ऐसी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद, राज्य सरकार एक अधिसूचना द्वारा या किसी अन्य तरीके से, जो निर्धारित किया जा

सकता है, अधिसूचित क्षेत्र को घोषित कर सकती है। धारा 5 या उसके किसी भी हिस्से को धारा 5 या उसके किसी हिस्से के तहत अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक अधिसूचित बाजार क्षेत्र माना जाएगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष कृषि उपज को धारा 5 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया है, तो उक्त क्षेत्र या उपज को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत अधिसूचना में शामिल नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में दिया गया आदेश यह है कि सरकार अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचित क्षेत्र या उसके किसी हिस्से को अधिसूचित बाजार क्षेत्र घोषित कर सकती है। धारा 5 या उसके हिस्से के तहत, इस प्रकार किसी क्षेत्र या कृषि उपज को शामिल करने की कोई शक्ति नहीं है, जो क्षेत्र या कृषि उपज, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था।

(7) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) वे प्रावधान हैं जिन पर मुख्य भरोसा मार्केट कमेटी के विद्वान वकील श्री पी.एस. जैन द्वारा किया जा रहा है। उनका तर्क है कि यदि अधिनियम की धारा 5 या 6 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन में कोई चूक या कोई अनियमितता या दोष है, तो उक्त चूक, अनियमितता या दोष को नजरअंदाज करना होगा। यह तर्क दिया गया है कि 1972 की रिट याचिका संख्या 1183 के साथ अधिनियम की धारा 5, अनुबंध 'ए' के तहत

जारी अधिसूचना में क्षेत्र हिसार हदबस्त संख्या 146 का उल्लेख नहीं करना वास्तव में एक चूक है, जिसे देखते हुए अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के प्रावधानों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। इस संबंध में पहला प्रश्न जो हल किया जाना है वह यह है कि अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) की सही व्याख्या क्या है, विशेषकर "प्रकाशन में किसी चूक के बावजूद" शब्दों की। ज्ञात हो कि अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के पूर्व भाग में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अधिनियम की धारा 5 या 6 के तहत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना पूर्ण रूप से प्रभावी होगी जिसका अर्थ है यह प्रावधान मानता है कि अधिनियम की धारा 5 या 6 के तहत एक अधिसूचना, जैसा भी मामला हो, पहले ही जारी की जा चुकी है और यह वह जारी अधिसूचना है जिसमें चूक, अनियमितता या दोष को नजरअंदाज किया जाना है। यदि "प्रकाशित करने में किसी भी चूक के बावजूद" शब्दों का अर्थ यह निकाला जाता है कि भले ही अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई हो, तो इससे बेतुकापन हो जाएगा क्योंकि धारा 6 की उप-धारा (4) का पहला भाग, उस स्थिति में, निरर्थक हो जाएगा और उक्त उपधारा के उस भाग पर कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता। इस स्थिति में, "प्रकाशित करने में किसी भी चूक के बावजूद" शब्दों का सामान्य अर्थ नहीं दिया जा सकता है और सबसे खराब व्याख्या यह होगी कि "प्रकाशन करने में किसी भी चूक के बावजूद" शब्दों को "प्रकाशन करने में किसी भी चूक के बावजूद" के रूप में पढ़ा जा सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि व्याकरण का सामान्य नियम जिस पर निर्माण आधारित है, को एक अपरिवर्तनीय नियम के

रूप में नहीं माना जा सकता है जिसे हमेशा और हर मामले में संदर्भ की परवाह किए बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि संदर्भ निश्चित रूप से सुझाव देता है कि व्याकरण का प्रासंगिक नियम लागू नहीं है, तो संदर्भ की आवश्यकता व्याकरण के नियम पर हावी होनी चाहिए। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बॉम्बे बनाम श्री कृष्णा मेटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, भंडारा (1) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य द्वारा ऐसा माना गया था। इसी प्रकार यह कानून का स्थापित नियम है कि बेहूदगी या असंगति से बचने के लिए कुछ परिस्थितियों में शब्दों के व्याकरणिक और सामान्य अर्थ से भी बचा जा सकता है। यह दृष्टिकोण राज्य बनाम सत राम दास (2) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा लिया गया था। इसलिए, अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) के शब्दों पर विचार करते समय यह स्पष्ट है कि "प्रकाशित करने के किसी भी चूक के बावजूद" शब्द का अर्थ यह नहीं होगा कि अधिनियम की धारा 5 या 6 के तहत अधिसूचना, जैसा भी मामला हो, प्रकाशित नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के शुरुआती वाक्य में उल्लिखित अधिसूचना जारी की गई है और इसके प्रकाशन में कोई चूक या अनियमितता या दोष है प्रकाशन में, घुस गया है, जिसे नजरअंदाज करना होगा।

(1) ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 1536.

(2) ए.आई.आर. 1959 पी.बी. 497.

(8) दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप का तर्क है कि अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) में "प्रकाशन की चूक" शब्द का अर्थ चूक माना जाना चाहिए । पंजाब कृषि उपज बाजार (सामान्य) नियम 1962 के नियम 7 में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के अलावा उस नियम में निर्दिष्ट एक या अधिक तरीकों से बोर्ड की ओर से निर्धारित किसी अन्य तरीके से अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना की प्रतियां आदेशों के तहत और अध्यक्ष के विवेक पर प्रकाशित की जाएंगी। हालाँकि, उनके द्वारा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) के शुरुआती वाक्य के अनुसार एक अधिसूचना आवश्यक रूप से जारी की जानी चाहिए, लेकिन उनका तर्क है कि यदि इरादे को प्रकाशित करने में कोई चूक हुई है पंजाब कृषि उपज बाजार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 7 में निर्धारित अन्य तरीके से अधिनियम की धारा 5 और 6' के तहत राज्य सरकार की ओर से, उस मामले में प्रकाशित करने की चूक को अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (4) के प्रावधानों के तहत नजरअंदाज किया जाना चाहिए । इस तर्क पर विद्वान वकील को इस स्थिति का सामना करना पड़ा कि यदि यह व्याख्या दी गई है, तो अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों में या अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत अधिसूचना के प्रकाशन का कोई अन्य तरीका निर्धारित नहीं है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना को छोड़कर और उस स्थिति में अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) में धारा 5 का उल्लेख अनावश्यक

हो जाएगा क्योंकि ऐसे किसी भी मामले की कल्पना नहीं की जा सकती है जहां आधिकारिक राजपत्र में कोई अधिसूचना जारी की गई हो। अधिनियम की धारा 5 और फिर भी प्रकाशन में कोई चूक हो सकती है क्योंकि अधिनियम की धारा 5 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत प्रकाशन का कोई अन्य तरीका प्रदान नहीं किया गया है क्योंकि पहले संदर्भित नियम 7 केवल की कार्रवाई पर लागू होता है। राज्य सरकार उपरोक्त धारा 6 के तहत अपने अंतिम इरादे को अधिसूचित कर रही है। विद्वान वकील को यह बताया गया कि भले ही यह व्याख्या दी गई हो, अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) के प्रावधानों को पूर्ण प्रभाव नहीं दिया जा सकता है और उस मामले में अनुभागों के संबंध में उल्लिखित प्रकाशन की चूक के संबंध में इस उपधारा में, पूरी तरह से निरर्थक और अर्थहीन हो जाएगा। इन टिप्पणियों पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के प्रारूपण में एक दोष है और उपधारा (4) में धारा 5 का उल्लेख वास्तव में एक दोष है। मसौदे में क्योंकि इस उपधारा में धारा 5 का कोई उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए था। जैसा कि पहले देखा गया है, यदि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दी गई व्याख्या को अपनाया जाता है, तो उक्त उपधारा का एक हिस्सा पूरी तरह से अनावश्यक हो जाता है और प्रावधानों की व्याख्या करते समय न्यायालय का प्रयास होना चाहिए कि वह कुछ अर्थ दे। व्याख्या को अपनाने के बजाय धारा के प्रावधानों का पालन करें जो धारा के एक बड़े हिस्से को अनावश्यक बना देगा।

(9) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि "प्रकाशित करने में कोई चूक" शब्द का अर्थ यह लिया जाता है कि यदि अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में चूक द्वारा किसी विशेष क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जारी अधिसूचना में वैध रूप से शामिल किया जा सकता है क्योंकि धारा 6 की उप-धारा (4) के प्रावधान, जो कि धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रावधानों को नकारात्मक कर देंगे। इस उप-धारा के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार कार्य करें, जो क्षेत्र धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में शामिल किया गया था, केवल उसे ही शामिल किया जा सकता है और कोई भी क्षेत्र, जो धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया है, किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता है। धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना में शामिल किया जाए। प्रथम दृष्टया विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क काफी आकर्षक प्रतीत होता है क्योंकि एक विशेष क्षेत्र जो अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में शामिल नहीं था, उस अधिसूचना के प्रकाशन में एक चूक मानी जाती है और उसी अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जारी अधिसूचना में शामिल किया जाना सही माना जाता है: उस स्थिति में कुछ क्षेत्र होंगे, जो हालांकि अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में शामिल नहीं हैं, फिर भी माना जाएगा अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जारी अधिसूचना में सही ढंग से शामिल किया गया है, लेकिन यदि प्रकाशन में चूक के महत्व को सही ढंग से सराहा जाता है, तो उस स्थिति में यह तर्क बल खो देता है। यह देखा जा सकता है कि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या किसी विशेष क्षेत्र के संबंध में अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन में कोई चूक हुई है और क्या सभी उपस्थित परिस्थितियां एक निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि वहां किसी विशेष क्षेत्र के संबंध में अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन में चूक हो गई है, उस स्थिति में अकेले अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत जारी अधिसूचना वैध होगी और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए संबंधित क्षेत्र माना जाएगा अधिनियम की धारा 6(4) के प्रावधानों के कारण अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में अधिसूचित किया गया है, जो प्रावधान करता है कि एक अधिसूचना को पूरी ताकत दी जाएगी और धारा 5 या 6 के तहत अधिसूचना को प्रभावी बनाया जाएगा। मामला अधिसूचना के प्रकाशन में किसी चूक या प्रकाशन में किसी अनियमितता या त्रुटि के बावजूद हो सकता है।

(10) इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह बहुत ही दुर्लभ मामलों में होगा जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जैसा कि वर्तमान मामले में उत्पन्न हुआ है, जिसके संबंध में मैं कई परिस्थितियों का उल्लेख करूंगा जो स्पष्ट रूप से एक निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं कि गैर-अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में हिसार हदबस्त संख्या 146 का उल्लेख स्पष्ट रूप से उस अधिसूचना के प्रकाशन में एक चूक है, जिस चूक को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। यह दलील कि अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में किसी विशेष क्षेत्र

के प्रकाशन में चूक हुई है, को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी याचिका उठाने वाले पक्ष को बाध्यकारी परिस्थितियों से दलील को साबित करना होगा कि यह वास्तव में एक चूक थी, और यदि न्यायालय संतुष्ट है कि यह एक चूक थी, तो धारा 6 की उप-धारा (4) का प्रावधान करना होगा लागू किया जाएगा और जो क्षेत्र चूक के कारण धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना से छूट गया था, उसे उक्त अधिसूचना में शामिल माना जाएगा। एक बार ऐसा हो जाने पर, धारा 6 की उप-धारा (1) का पूर्ण अनुपालन होगा जब उक्त क्षेत्र को अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी अधिसूचना में भी शामिल किया जाएगा।

(11) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जारी अधिसूचना में, इस रिट याचिका के साथ अनुबंध 'बी', और बाद की अधिसूचनाओं में भी, इस रिट याचिका के साथ अनुबंध 'डी' और 'ई' के तहत जारी किया गया है । हिसार हदबस्त के संबंध में क्रमशः अधिनियम की धारा 5 और 6(1) क्रमांक 146, वहां राज्य सरकार द्वारा इसका उल्लेख नहीं किया गया इस संबंध में धारा 5 के तहत अधिसूचना में एक चूक थी अधिनियम का, अनुबंध 'ए', और यह माना जाना चाहिए कि वहाँ था कोई चूक नहीं, फिर से बिना किसी योग्यता के है। यह इतना पवित्र नहीं था कि केवल इसलिए कि राज्य सरकार ने बाद की अधिसूचना में उल्लेख किया है कि पिछली अधिसूचना में एक चूक थी, इसे एक सत्य के रूप में लिया जाना चाहिए कि चूक हुई थी और इसी तरह यदि कुछ परिस्थितियाँ हैं दिखाएँ कि

कोई चूक थी, जो न्यायालय को उस निष्कर्ष पर आने से नहीं रोकेगी, भले ही राज्य सरकार बाद की अधिसूचना में इसका उल्लेख करने में विफल रही हो। अत: विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क निराधार है।

(12) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) की व्याख्या करते हुए इस प्रकार, एकमात्र अन्य प्रश्न जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या हिसार हेडबस्ट का उल्लेख न करने में कोई चूक हुई है । अधिसूचना में क्रमांक 146, इस रिट याचिका के साथ संलग्नक 'ए', ''अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रकाशित, एक प्रकार की चूक है जिसे अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के तहत माफ किया जा सकता है । मेरी राय में, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रकाशित अधिसूचना अनुलग्नक 'ए' में हिसार हदबस्त संख्या 146 का उल्लेख न किया जाना गलत है। स्पष्ट रूप से एक चूक जिसे धारा 6(4) के तहत नजरअंदाज किया जा सकता है, कार्य करें क्योंकि ऐसी कई परिस्थितियाँ हैं जो उस निष्कर्ष तक ले जाती हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति तो यह है कि माना वह क्षेत्र जहां याचिकाकर्ता बिक्री, खरीद, का कारोबार कर रहे हैं कृषि उपज का भण्डारण एवं प्रसंस्करण जो कि हिसार नगर निगम सीमा हैडबस्ट नं 146 मार्केट कमेटी, हिसार की सीट थी और है । जैसा कि 1939 के अधिनियम संख्या V के तहत मार्केट कमेटी की ओर से दायर रिटर्न के साथ संलग्न अधिसूचना अनुलग्नक 'आर-आई' से

स्पष्ट है, जो 1961 के अधिनियम संख्या 23 के अधिनियमन द्वारा निरस्त कर दिया गया है, मार्केट कमेटी हिसार इसके बाज़ार क्षेत्र में नगरपालिका क्षेत्र हिसार हदबस्त नंबर 146 शामिल था और बाज़ार समिति, हिसार की सीट उस क्षेत्र में स्थित थी। 1961 के अधिनियम संख्या 23 के लागू होने के बाद भी ऐसी ही स्थिति है। जिस बाजार क्षेत्र के संबंध में अधिसूचनाएं, अनुलग्नक 'ए' और 'बी' जारी की गई हैं, उसे मार्केट कमेटी हिसार का नाम दिया गया है और उक्त मार्केट कमेटी की सीट है स्वीकार्य रूप से उस क्षेत्र में स्थित है जैसा कि अधिसूचना अनुबंध 'आर-2' से स्पष्ट है। फ़ाइल में यह भी स्वीकार किया गया है और साबित किया गया है कि अधिनियम के तहत घोषित, हिसार मार्केट कमेटी का मुख्य बाज़ार यार्ड, इस क्षेत्र के भीतर है। अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी करते समय राज्य सरकार की यह मंशा नहीं हो सकती कि हिसार नगरपालिका क्षेत्र हदबस्त नंबर 146 जो कि मार्केट कमेटी, हिसार की सीट थी और जिसे घोषित किया जा रहा था, को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। बाजार क्षेत्र ही. यह नहीं माना जा सकता कि यद्यपि इस क्षेत्र में मुख्य बाजार यार्ड स्थापित किया गया है फिर भी सरकार का इरादा इस क्षेत्र में कृषि उपज की बिक्री, खरीद, भंडारण और प्रसंस्करण पर नियंत्रण रखने का नहीं है।

(13) दूसरे, अधिनियम की योजना से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 25 के तहत गठित बाजार विकास निधि का उपयोग अधिनियम की धारा 26 में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए

किया जाना है जिसमें बेहतर सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। कृषि उपज का विपणन और अन्य विभिन्न सुविधाएं जैसे पक्का फर्श और बाजार क्षेत्र में नालियों का प्रावधान और अन्य सुविधाएं। यह साबित हो गया है कि मुख्य मार्केट यार्ड नगरपालिका क्षेत्र हिसार हदबास्ट नंबर 146 में स्थित है और मार्केट कमेटी की ओर से दाखिल रिटर्न के पैरा 9 (ई) में उल्लिखित कई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बाज़ार समिति का इरादा ऐसे क्षेत्र पर बाज़ार निधि खर्च करने का नहीं हो सकता है जिसे बाज़ार क्षेत्र में ही शामिल नहीं किया जाना था और जहाँ, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, खरीद, बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण किया जाता था। कृषि उपज को विनियमित नहीं किया जा सका।

(14) तीसरा, यह ध्यान देने योग्य है कि अधिसूचना में, इस रिट याचिका के साथ अनुबंध 'बी', अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी होने के लगभग '8 महीने बाद अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जारी किया गया है। ,हिसार हेडबस्ट नंबर 146 को शामिल किया गया है। यदि धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में बाजार क्षेत्र को शामिल करना एक चूक नहीं थी, तो इसका कोई कारण नहीं है कि इस क्षेत्र को अल्प अवधि के भीतर अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत जारी अधिसूचना में क्यों शामिल किया जाना चाहिए था। धारा 5 के तहत अधिसूचना जारी होने के 8 महीने बाद। यह भी स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत अधिसूचना, अनुबंध 'सी', धारा 6 (1) के तहत जारी अधिसूचना के संदर्भ में जारी की गई थी,

जिसमें अधिसूचना में बाजार क्षेत्र के भीतर हिसार हेडबस्ट नंबर 146 शामिल था और नहीं वर्ष 1972 तक, जब ये रिट याचिकाएँ दायर की गई थीं, सभी आपत्तियों को अधिनियम की धारा 6(1) या 11 और 12 के तहत जारी अधिसूचनाओं पर ले जाया गया था, जो अधिसूचनाएँ वर्ष 1962 में जारी की गई थीं। पक्षों के बीच यह भी स्वीकार किया गया मामला है कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ अन्य सभी लाइसेंसधारी जिनके व्यावसायिक परिसर नगरपालिका क्षेत्र हिसार हेडबास्ट नंबर 146 के भीतर स्थित हैं, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं और भुगतान कर रहे हैं। मार्केट कमेटी को मार्केट फीस। 1970 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा इस धारा में संशोधन किए जाने से पहले याचिकाकर्ताओं सहित सभी लाइसेंसधारक अधिनियम की धारा 12 के तहत डीलर-लाइसेंसधारकों में से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए पंजीकृत मतदाता थे, जिसमें सदस्यों के चुनाव के बजाय नामांकन प्रदान किया गया था। मार्केट कमेटी द्वारा दायर रिटर्न से यह भी स्पष्ट है कि हरियाणा संशोधन अधिनियम संख्या 25 1970 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 12 में संशोधन के बाद अधिनियम की धारा 10 के तहत लाइसेंसधारियों में से चार सदस्य, जो सभी निवासी हैं हैडबस्ट 146, हिसार में अधिनियम की धारा 12 के तहत मार्केट कमेटी में नामांकित किया गया है।

(15) चौथा कारक, जो भी इसी निष्कर्ष पर ले जाता है, वह यह है कि जब सरकार के ध्यान में यह बात आई कि धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में हिसार हेडबस्ट नंबर 146 का नाम शामिल नहीं करने में चूक हुई है। अधिनियम, अनुबंध 'ए' इस रिट याचिका के साथ, एक और अधिसूचना दिनांक 11 मार्च, 1964, अनुबंध 'डी' अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी की गई थी जिसमें सरकार ने (हिसार हदबास्ट नंबर 146 को बाजार में शामिल करने के अपने इरादे को अधिसूचित किया था) क्षेत्र, हिसार और 20 अगस्त, 1964 को, सरकार के प्रस्ताव पर किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई, अधिनियम अनुबंध 'ई' की धारा 6 (1) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत हिसार हेडबास्ट नंबर 146 को बाजार में शामिल किया गया। क्षेत्र, हिसार। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप का तर्क है कि अधिसूचना, अनुबंध 'ए' में, केवल 149 गांवों को अधिसूचित किया गया था और अधिसूचना, अनुबंध 'बी' में, धारा 6 (1) के तहत जारी किया गया था। अधिनियम के अनुसार, 169 गांवों को अधिसूचित किया गया है, जिसमें हिसार हदबस्त नंबर 146 भी शामिल है, इसलिए, इसे नहीं माना जाना चाहिए । चूक, बिना किसी योग्यता के है। वर्तमान याचिकाओं में, हमें केवल इस बात की चिंता है कि क्या अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना में हिसार हेडबास्ट संख्या 146 को शामिल न किया जाना, अनुलग्नक 'ए' एक लोप है या नहीं। अधिसूचना के क्रमांक 150 से 169 तक अन्य गांवों के बाजार क्षेत्र के संबंध में निर्णय से हमें कोई सरोकार नहीं है। वर्तमान रिट याचिकाओं में अनुबंध 'बी'। इन रिट याचिकाओं में हमारे

सामने संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचना में हिसार बियर हदबास्ट संख्या 145 का उल्लेख होने के बावजूद, हिसार हदबस्त संख्या 146 का उल्लेख न किया जाना एक चूक है या नहीं। सभी कारक, जो मैंने पहले ही गिनाए हैं, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अधिसूचना अनुलग्नक 'बी' जारी करते समय राज्य सरकार को यह मानना मुश्किल है। अधिनियम की धारा 5 के तहत, मार्केट कमेटी, हिसार के बाजार क्षेत्र के भीतर हिसार हेडबस्ट नंबर 146 को शामिल करने का कोई इरादा नहीं था। यह भी स्पष्ट है कि अधिसूचना अनुलग्नक 'डी' और 'ई', जो क्रमशः अधिनियम की धारा 5 और (6) (1) के तहत वर्ष 1964 में जारी किए गए थे, उनमें बाजार क्षेत्र में हिसार हेडबस्ट नंबर 146 शामिल था। अनुलग्नक 'डी' में क्रम संख्या 150 से 169 तक उल्लिखित एक को छोड़कर अन्य गांवों को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, उपरोक्त संदर्भित कारक, जो कि हिसार हेडबास्ट नंबर 146 के मामले में उपलब्ध हैं, उन मामलों में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और जब भी ऐसे प्रश्न उठेंगे, उस मामले पर उचित रूप से विचार किया जा सकता है, लेकिन प्रयोजनों के लिए वर्तमान रिट याचिकाओं के निपटान से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 5 के तहत जारी अधिसूचना, अनुलग्नक 'ए' में हिसार हेडबास्ट नंबर 146 का उल्लेख न करना वास्तव में एक चूक थी और यह नहीं माना जा सकता कि राज्य सरकार का इस क्षेत्र को मार्केट कमेटी, हिसार के तहत बाजार क्षेत्र में शामिल करने का कोई इरादा नहीं था, जो प्रमुख मार्केट यार्ड और मार्केट कमेटी, हिसार की सीट है।

(16) मामले को दूसरे नजरिये से भी देखा जा सकता है । केवल आपत्ति जो मार्केट कमेटी, हिसार, अधिसूचना अनुलग्नक के मद्देनजर अधिकार क्षेत्र को लेकर ली गई है, अधिनियम की धारा 5 और 6 (1) के तहत जारी 'डी' और 'ई' का मतलब यह है कि अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत राज्य सरकार द्वारा 'डी' और 'ई' अधिसूचना जारी होने के बाद बाजार क्षेत्र के लिए बाजार समिति की स्थापना की अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। यह बताया जा सकता है कि धारा 11 और 12, अनुबंध 'सी' के तहत जारी अधिसूचना में, अधिनियम की धारा 6 (1), अनुबंध 'बी' के तहत जारी एक अधिसूचना का संदर्भ दिया गया है, जिस अधिसूचना में निश्चित रूप से मार्केट कमेटी, हिसार के मार्केट एरिया नंबर 146 हिसार हेडबस्ट शामिल है । इसलिए, मेरी राय में इस मामले को किसी भी कोण से देखा जाए, यह मानना मुश्किल है कि हिसार हेडबास्ट नंबर 146 मार्केट कमेटी, हिसार के बाजार क्षेत्र के भीतर गर्म है, क्योंकि यह अब धारा 11 और 12 के तहत कार्यवाही करना गठित है।

(17) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का यह तर्क कि हिसार हदबास्ट नंबर 146 के लिए कोई कानूनी रूप से गठित मार्केट कमेटी नहीं है, अधिनियम के प्रावधानों का निर्माण बहुत तकनीकी होगा जो व्यावहारिक रूप से उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए कृषि उत्पाद बाज़ार अधिनियम, 1961 अधिनियमित किया गया है। ऐसी अनिवार्यता को पूरा

करने के लिए विधानमंडल द्वारा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के प्रावधानों को धारा 5 और 6(1) के तहत अधिसूचनाओं के प्रकाशन में कुछ चूक, अनियमितताओं या दोषों को नजरअंदाज करने के लिए अधिनियमित किया गया है।) अधिनियम का. इसलिए, रिट याचिकाओं को इस आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती है कि हिसार हदबस्त नंबर 146 क्षेत्र के लिए कोई कानूनी रूप से गठित मार्केट कमेटी नहीं है और इस तरह इस तर्क में कोई दम नहीं है कि मार्केट कमेटी बाजार शुल्क नहीं लगा सकती है और याचिकाकर्ता हैं समान भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(18) मार्केट कमेटी के विद्वान वकील श्री पी.एस. जैन द्वारा उठाया गया दूसरा तर्क यह है कि याचिकाकर्ताओं को मार्केट कमेटी, हिसार की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती देने से रोका जाता है, जैसा कि लिखित बयान के पैरा 9 में दिया गया है। बाजार समिति की ओर से दायर याचिकाओं को याचिकाकर्ताओं द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है, जिसका आशय यह है कि याचिकाकर्ताओं ने उक्त बाजार समिति से आवेदन करके लाइसेंस लिया था और बाजार समिति ने इसके विकास पर पर्याप्त राशि खर्च की थी। मुख्य बाजार यार्ड और उप-बाजार यार्ड, जिसका याचिकाकर्ता मुख्य बाजार यार्ड में तैयार क्रेताओं और विक्रेताओं के साथ लाभ उठा रहे हैं और मार्केट कमेटी, हिसार द्वारा प्रदान की गई अन्य सुविधाएं, जैसे पक्की सड़कें, पक्की फर्श और सुविधाएं प्रदान करना। नालियाँ, पानी की आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल,

स्वच्छता व्यवस्था, पीने के पानी के लिए वाटर कूलर और मवेशियों को डराने की मशीन आदि आदि की व्यवस्था, और वे वर्ष 1962 से इन सभी लाभों का आनंद ले रहे हैं, उन पर बाजार समिति के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने से रोक दिया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि कई मामलों में याचिकाकर्ता और अन्य लाइसेंसधारी, नियमों के अनुसार, बाजार शुल्क एकत्र कर रहे थे, जो उन्होंने बाजार समिति को भुगतान किया था और चूंकि वे स्वयं नियमों के तहत बाजार शुल्क एकत्र कर रहे थे। अधिनियम, इसलिए, वे अब बाजार समिति के क्षेत्राधिकार को चुनौती नहीं दे सकते। विद्वान वकील एस. नंद सिंह बनाम रहमत दीन और अन्य, (3) बापटला वेंकट सुब्बा राव बनाम सिखराम रामकृष्ण राव और अन्य (4), मिर्जा नौशेरवान खान और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (5) पर भरोसा करते हैं। , असीज़ रॉथर बनाम कंजिरापल्ली पंचायत (6) और द स्टेट बनाम केशव चंद्र नस्कर, (7) इस प्रस्ताव के समर्थन में। दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप ने तर्क दिया कि यदि

(3) ए.आई.आर. 1946 एल.ए.एच.73.

(4) ए.आई.आर. 1958 ए.पी. 322.

(5) ए.आई.आर. 1959 ए.पी. 444.

(6) ए.आई.आर. 1961 केरेला 289.

(7) ए.आई.आर. 1962 कलकत्ता 338.

यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बाजार समिति का विधिवत गठन नहीं किया गया है और इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो कानून के खिलाफ किसी भी रोक का कोई सवाल ही नहीं है। याचिकाकर्ता, याचिकाकर्ता उनके द्वारा भुगतान किए गए बाजार शुल्क को वापस पाने के हकदार हैं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। विद्वान वकील इस प्रस्ताव के लिए अशोक मार्केटिंग लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य (8) पर भरोसा करते हैं।

(19) मेरी राय में मार्केट कमेटी के विद्वान वकील जिन अधिकारियों पर भरोसा करते हैं, वे उनके लिए काफी मददगार नहीं हैं।; कानून के विरुद्ध कोई रोक नहीं लगाई जा सकती. यदि याचिकाकर्ता यह दिखाने में सफल हो जाते हैं कि हिसार हेडबास्ट नंबर 146 मार्केट कमेटी, हिसार के बाजार क्षेत्र के भीतर नहीं है, तो जाहिर तौर पर मार्केट कमेटी, हिसार का याचिकाकर्ताओं पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। उस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी भी तरह की सहमति मार्केट कमेटी को अधिकार क्षेत्र का अधिकार नहीं दे सकती है, जिसे वांछित माना जाता है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को इस प्रारंभिक आपत्ति पर खारिज नहीं किया जा सकता है और इसलिए, योग्यता के आधार पर तर्कों की जांच की गई है।

(20) एकमात्र अन्य मामला, जिसे पार्टियों के विद्वान वकील को पूरी निष्पक्षता से संदर्भित

(8) ए.आई.आर. 1971 एस.सी. 946.

किया जा सकता है, वह यह है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया था कि 1972 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12, जो पारित हो चुका है पूरे हरियाणा राज्य में, जहां भी यह लागू हो, बाजार समिति द्वारा बाजार शुल्क के संग्रह को वैध बनाने के लिए, यह संविधान के दायरे से बाहर है क्योंकि अधिनियम ने समिति के संविधान में मूल दोष का समाधान नहीं किया है और इस प्रकार, बाजार शुल्क का आरोपण और संग्रहण मान्य नहीं होगा। दूसरी ओर उक्त अधिनियम की व्याख्या श्री चेतन दास दीवान, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा की गई है; उन्होंने कहा कि यदि बाजार समिति के गठन में कोई खामी है तो उसे अधिनियम के तहत दूर कर दिया गया है, इसलिए बाजार शुल्क लगाने और संग्रह करने की वैधता पूरी तरह से वैध है। मेरे इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि मार्केट कमेटी, हिसार के संविधान में कोई दोष नहीं है, इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह अधिनियम तभी लागू होता यदि यह पाया जाता कि समिति के संविधान में कानूनी दोष था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम वर्तमान मामले पर लागू नहीं है। किसी उचित मामले में अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है।

(21) हमारे सामने कोई अन्य बिंदु नहीं रखा गया है।

फर्म हनुमान दल एंड जनरल मिल्स, बालसमंद रोड, हिसार बनाम मार्केट कमेटी, हिसार, आदि (जस्टिस ढिल्लों)

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2

(22) ऊपर दर्ज कारणों से, इन सभी रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं है और इन्हें खारिज किया जाता है। हालाँकि, मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

जस्टिस पंडित - मैं सहमत हूं कि रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाएंगी, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता महाजन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कैथल, हरियाणा

फर्म हनुमान दल एंड जनरल मिल्स, बालसमंद रोड, हिसार बनाम मार्केट कमेटी, हिसार, आदि (जस्टिस ढिल्लों)

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1975) 2